भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

07.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2363 का उत्तर

माल ढुलाई रेल संभारतंत्रों का आधुनिकीकरण

2363. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संभारतंत्र क्षमता बढ़ाने और परिवहन की लागत कम करने के लिए माल ढुलाई रेल अवसंरचना की व्यापक समीक्षा की है;

(ख) क्या प्रमुख माल ढुलाई गलियारों पर भीड़भाड़ का प्रभाव औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात में प्रतिस्पर्धा की क्षमता पर पड़ रहा है;

(ग) मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल का विस्तार करने, माल ढुलाई को स्वचालित करने और रेल संभारतंत्र प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय स्तर पर माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालिक कार्यनीति बनाई गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): माल ढुलाई संभार तंत्र सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ाने और रेलवे के माल ढुलाई हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, भारतीय रेल ने माल ढुलाई दक्षता बढ़ाने, निर्बाध क्षेत्रीय संपर्कता सुनिश्चित करने तथा मजबूत आरंभिक और अंतिम-मील समाधान प्रदान करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति लागू की है। प्रमुख पहलें निम्नानुसार वर्गीकृत हैं-

(i) टर्मिनल विकास: टर्मिनलों पर रेल माल ढुलाई की दक्षता में सुधार के लिए, भारतीय रेल ने दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाया है: गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति के तहत आधुनिक रेल माल ढुलाई टर्मिनलों के विकास को प्रोत्साहित करना और रेलवे के स्वामित्व वाले माल शेडों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना/उन्नत करना।

निजी निवेश के माध्यम से कार्गो टर्मिनलों स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई है। गति शक्ति टर्मिनलों का स्थान का निर्णय उद्योग से प्राप्त होने वाली मांग, कार्गो यातायात की क्षमता, रेलवे अवसंरचना की उपलब्धता और क्षेत्र की समग्र संभार क्षमता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

अभी तक, प्रति वर्ष 224 मिलियन टन (एमटीपीए) अनुमानित माल सम्हलाई क्षमता वाली 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) को कमीशन किया जा चुका है। इस नीति के अंतर्गत इन गति शक्ति टर्मिनलों के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रु. का निजी निवेश जुटाया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान इन गति शक्ति टर्मिनलों में 146 मिलियन टन (एमटी) माल यातायात की सम्हलाई की गई।

(ii) वैगन निवेश योजनाएं: भारतीय रेल ने पहले से ही निजी क्षेत्रों हेतु वैगनों में निवेश करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जिसमें सीमेंट, तेल, स्टील, फ्लाई-ऐश आदि के लिए वैगन जैसी पण्य केंद्रित विशेष वैगन शामिल हैं। अब तक, विशेष प्रयोजन वैगनों के लगभग 275 रेक और सामान्य प्रयोजन वाले 397 रेक परिचालन में हैं, जिनसे थोक सीमेंट, फ्लाई-ऐश, स्टील उत्पादों, लौह अयस्क और कोयला आदि जैसी वस्तुओं में मॉडल हिस्सेदारी में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा, ऑटोमोबाइल के परिवहन के लिए एक अलग योजना है जिसके तहत उद्योग के स्वामित्व वाले लगभग 54 रेक परिचालन में हैं।

(iii) संयुक्त पार्सल उत्पाद- रैपिड कार्गो सेवा (जेपीपी-आरसीएस) योजना: यह योजना ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और घर-घर पार्सल सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुकूलित संभार प्रदान करती है। योजना के तहत, 'वर्चुअल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म (वीएपी)' पर एग्रीगेटर्स (भारतीय डाक के अलावा) के माध्यम से इन सेवाओं में पार्सल स्थान की ऑनलाइन बुकिंग का प्रावधान किया गया है।

(iv) कॉनकोर, रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो दिल्ली-कोलकाता और मुंबई-कोलकाता सेक्टरों पर जेपीपी-आरसीएस का उपयोग करके घर-घर पार्सल सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। कॉनकोर सोनिक गुड्स शेड में एक पायलट परियोजना के तहत घर-घर संभार भी प्रदान कर रहा है।

बजट आबंटन और नेटवर्क विस्तारः-

पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल द्वारा रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया है। भारतीय रेल में नए रेलपथ को चालू करने/बिछाने का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	चालू किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ को चालू करने की औसत दर
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रतिदिन
2014-26	36,429 कि.मी.	8.32 कि.मी. प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में लगभग 8.31 लाख करोड़ रुपए की लागत पर कुल 40,000 किलोमीटर की लंबाई की 514 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (169 नई लाइन, 29 आमान परिवर्तन और 316 दोहरीकरण) स्वीकृत हैं। इसका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	नई लाइन/बड़ी लाइन/दोहरीकरण की कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2026 तक चालू की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक कुल व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	169	16,634	3,361	1,57,572
आमान परिवर्तन	29	3,987	3,045	24,227
दोहरीकरण	316	19,379	6,177	1,23,454
कुल	514	40,000	12,583	3,05,253

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर: रेल मंत्रालय ने दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अर्थात् लुधियाना से सोननगर तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (1337 कि.मी.) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से दादरी तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (1506 कि.मी.) का निर्माण शुरू किया है। दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अर्थात् ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (1337 कि.मी.) और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (1506 कि.मी.) को चालू कर दिया गया है।

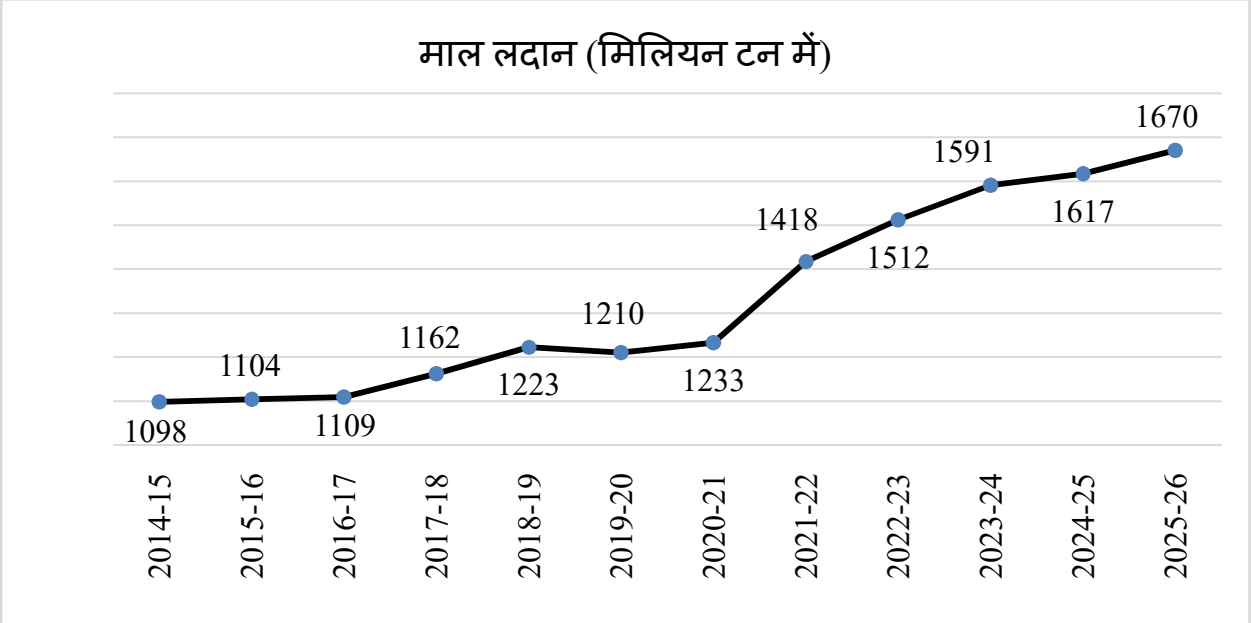
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर औसतन प्रतिदिन 443 से अधिक गाड़ियों का परिचालन किया जाता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने सुदृढ़ परिचालनिक कार्य निष्पादन का प्रदर्शन किया है। औसत गति बढ़ने, तीव्रतर टर्नअराउंड और विश्वसनीयता में वृद्धि होने से माल ढुलाई की मात्रा में

लगातार वृद्धि हुई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने माल ढुलाई यातायात को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अंतरित कर पारंपरिक नेटवर्क पर अतिरिक्त रेलपथ बनाने में योगदान दिया है। इसके परिणामस्वरूप, रेलवे अपने नेटवर्क पर अतिरिक्त माल और कोचिंग सेवाएं चलाने में सक्षम रही है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना का परिवहन और संभार क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह डबल स्टैक कंटेनर (डीएससी) गाड़ियों की बेहतर आवाजाही, उच्च एक्सल लोड गाड़ियों, पश्चिमी बंदरगाहों द्वारा उत्तर के अंदरूनी इलाकों तक तेजी से पहुंच और डीएफसी के साथ उद्योगों के नए टर्मिनलों/लिंकों के विकास को सक्षम करेगा।

केंद्रीय बजट 2026 में पूर्व में डानकुनि से पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इस कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार/अद्यतन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
पिछले कुछ वर्षों में माल लदान और राजस्व बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। 2014 से माल लदान निम्नानुसार है:

वर्ष	माल लदान (मिलियन टन में)
2014-15	1098
2015-16	1104
2016-17	1109
2017-18	1162
2018-19	1223
2019-20	1210
2020-21	1233
2021-22	1418
2022-23	1512
2023-24	1591
2024-25	1617
2025-26	1670



2025-26 में भारतीय रेल की माल ढुलाई बढ़कर 1,670 मीट्रिक टन हो गई है, जिससे भारतीय रेल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माल ढुलाई करने वाली रेलवे बन गई है।

****